श्री अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न दिनांक- 05.01.2016 (मंगलवार) को हुई वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही के सामान्य बिन्दु:-

1. **इंदिरा आवास योजना**

➢ वित्तीय वर्ष- 2015-16 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा की गई । अबतक कुल 1,87,783 आवासों की स्वीकृति की जानकारी दी गई । आवास स्वीकृति में पिछड़े जिलों यथा समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, दरभंगा, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर पर विशेष अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया ।
➢ इंदिरा आवास कर्मियों के मानदेय भुगतान से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक- 08.01.2016 तक सभी जिलों से प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।
➢ अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु जिलावार/प्रखंड विकास पदाधिकारीवार/ इंदिरा आवास कर्मीवार लक्ष्य का निर्धारण कर अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया । इस संबंध में एक प्रपत्र तैयार कर जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं इसका साप्ताहिक अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया ।
➢ पुराने अपूर्ण आवासों का पूर्ण कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिये गये दिशा-निर्देश को पुन: सभी जिलों को भेजे जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन:- राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी)

2. **मनरेगा**

➢ प्रतिदिन 3.50 लाख मानव दिवस सृजन करने की जानकारी प्रदान की गई । मनरेगा अंतर्गत पुन: जिलों को रैंकिंग करने हेतु कार्य योजना बनाने का निदेश दिया गया ।
➢ द्वितीय किस्त के प्रस्ताव हेतु जिलों से Audit Report प्राप्त कर 15 जनवरी 2016 तक प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे जाने हेतु सभी उप विकास आयुक्तों एवं उनके संबंधित अंकेक्षकों के साथ दिनांक- 08.01.2016 को VC की तिथि निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
➢ जिलावार नियुक्त मनरेगा कर्मियों के मानदेय भुगतान के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन: विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, एवं मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक)

3. **Block Building**

➢ NABARD से प्राप्त स्वीकृति संबंधी सूचना के आलोक में 25 आई0टी0 भवनों की स्वीकृति हेतु अविलम्ब संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ।
➢ स्वीकृति हेतु वैसे प्रखंड जहाँ पूर्व से कोई संरचना आदि नहीं हो तथा वैसे प्रखंड जहाँ पर भूमि उपलब्ध होने का प्रस्ताव प्राप्त हो, को प्राथमिकता दिये जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी)

4. CAG Reports/PAC Paras

➢ जिलों में लंबित AC/DC विपत्रों के समायोजन तथा लंवित UC की समीक्षा करते हुए उसका निष्पादन करने का निदेश दिया गया।
➢ CAG/PAC के लंवित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु की गई से समीक्षा से संबंधित कार्यवाही की प्रति सभी प्रशाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी)

5. **Court Cases**

➢ प्रशाखावार लंवित मामलों की जानकारी प्राप्त की गई एवं उसे IWDMS पर निष्पादित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - संजय कुमार सिंह, उप सचिव एवं सरोज कुमार, IT Director)

6. **IWDMS/e-office**

- एक अप्रैल 2016 से विभाग में e-office लागू कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से भी सभी जानकारी प्राप्त करने निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - चेत नारायण राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, सरोज कुमार, IT Director एवं सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर)

7. **विधान सभा/विधान मंडल से संबंधित प्रश्न**

- सभी लंबित 172 प्रश्नों की श्रेणीवार विवरणी प्रस्तुत किया गया ।
- विधान सभा से संबंधित सभी मामलों की सप्ताहिक रूप से समीक्षा कर इसे निष्पादित करने का निदेश विशेष सचिव को दिया गया ।

(अनुपालम - प्रमोद कुमार बिहारी, विशेष सचिव एवं विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी)

8. **स्थापना**

- स्थापना से संबंधित सभी मामलों यथा सभी प्रकार के अवकाश संबंधी आवेदन, पदस्थापन के संबंध में प्रतीक्षारत कर्मी/पदाधिकारी, सेवा विनियमन आदि से संबंधित मामलों का Matrix बनाकर जानकारी उपलब्ध कराई गयी । निदेश दिया गया कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में भी संबंधित प्रशाखा समरूप कार्रवाई करेंगे ।
- सेवानिवृत पदाधिकारियों के देय लाभ का भुगतान दो सप्ताह के अंदर करने का निदेश दिया।
- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों एवं अन्य पर्यवेक्षीय संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवा विनियमन की कार्रवाई दो सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया गया ।
- जिन पदाधिकारियों के संबंध में विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित है एवं जो लधु दंड के दायरे में आते हैं उस हेतु अविलम्व कार्रवाई की जाय ।
- प्रतिक्षारत 16 RDOs के पदस्थापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।
- ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के वेतन भुगतान से संबंधित संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ।
- जिन ग्रामीण विकास पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र दिया गया है, उस पर भी अविलम्व कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।
- पंचायत रोजगार सेवकों के पुनर्नियोजन से संबंधित संचिका पर भी आवश्यक कार्रवाई हेतु follow-up करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी, विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी, मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं जगदीश चौधरी, अवर सचिव)

9 **BISPS/BRDS**

- **BISPS/BRDS** हेतु किये जाने वाले कार्य, उसके उद्देश्य एवं इस संबंध में अद्यतन किये गये कार्य के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।
- पूर्व में एक टीम का गठन कर यादृच्छिक रूप से 5 प्रखंडों का चयन कर उनके लेखा संबंधी सभी आकड़ों की जॉच कराकर General Cash Book के अंतिम पृष्ठ की फोटो कॉपी उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में एक Presentation/Write-up प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था । यह कार्य उनके द्वारा एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - सी0पी0 खंडुजा, निदेशक सामाजिक वानिकी, चेत नारायण राय, विशेष कार्य पदाधिकारी, विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक)

10. **DPAP/IWDP**

- जिलावार समीक्षा कर DPAP/IWDP से संबंधित सभी मामलों की समाप्ति हेतु कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क कर त्रुटियों का निराकरण करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - सी0पी0 खंडुजा, निदेशक सामाजिक वानिकी एवं राधाकांत कुमार, परियोजना निदेशक)

11. **VSAT**

- अरवल जिला के कलेर एवं गया जिला के डुमरिया प्रखंड में VSAT के स्थापना हेतु निर्मित राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के लिए रोड परमिट निर्गत किये जाने के पश्चात् इस कार्य पर सतत अनुश्रवण कर इसको functional कराने का पुन: निदेश दिया गया ।

(अनुपालन:- सरोज कुमार, IT Director)

12. **जन शिकायत**

- लंवित शिकायतों के निष्पादन से संबंधित "समाधान" सॉफ्टवेयर सिस्टम एवं BPGRS का अध्ययन किया गया है, इस संबंध में दिनांक- 06.01.2016 को अप0 में विमर्श करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन:- विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं सरोज कुमार, IT Director)

13. **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) एवं IPPE II**

- सभी जिलों में पंचायत सचिव एवं छूटे हुए कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई । निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम जिलों में GPDP हेतु राशि उपलब्ध करा दी जाय ।
- सभी जिलों से विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में हो रहे प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया । इस कार्य में निम्न प्रगति वाले 5 जिलों को चिन्हित करते हुए प्रतिदिन इसकी सूचना दिये जाने का निदेश दिया ।
- सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त डाटा के डिजिटाईजेशन (डाटा इंट्री) हेतु सभी जिलों को ट्रेनिंग दिये जाने का निदेश दिया गया एवं इस कार्य को संपन्न करने हेतु सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने का निदेश दिया गया ।

(राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी, कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं शुभेन्द्र सान्याल, UNDP Consultant)

5/1/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक 257300 पटना दिनांक 05-01-2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.1.16

(अभ्येन्द्र मोहन सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी